



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राचिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] तई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 2, 1970/प्रियन 10, 1892

No. 171] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 2, 1970/ASVINA 10, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती है जिससे कि यह असत्तर संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd October 1970

G.S.R. 1756.—The following Proclamation by the President is published for general information:

Whereas I, V. V. Giri, President of India, have received a report from the Governor of the State of Uttar Pradesh and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(771)

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to objects of this Proclamation, namely:—

- (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to much extent as I think fit through the Governor of the said State;
- (ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—
 - so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;
 - so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India; articles 163 and 164;
 - so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State; article 167;
 - so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State clause (1) of article 174, articles 175, 176 and 177, clause (c) of article 179 and the first proviso thereto, article 181, clause (c) of article 183 and the proviso thereto, articles 185, 188, 189, 193, 194 and 196 to 198 (both inclusive), articles 200 and 201, articles 208 to 211 (both inclusive), the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and
 - so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;
- (iii) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the reference in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (1) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or Laws made in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and the United Provinces General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

Camp Kiev (U.S.S.R.)
The 1st October, 1970.

V. V. GIRI,
President.

[No. 38/12/70-Pol. I(A).]

NEW DELHI;
The 2nd October, 1970.

L. P. SINGH, Secy.

ORDER

New Delhi, the 2nd October 1970

G.S.R. 1757.—The following Order made by the President is published for general information:

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 1st day of October, 1970 by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Uttar Pradesh and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

Camp Kiev (U.S.S.R.)

The 1st October, 1970.

V. V. GIRI,
President.

NEW DELHI;
The 2nd October, 1970.

[No. 38/12/70-Pol. I(A).]
L. P. SINGH, Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर 1970

जो० एस० आर, 1756.—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वेसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :

यह: मुझे, वी० वी० गिरि, भारत के राष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है तथा उस प्रतिवेदन पर श्रीमृग्नी प्राप्त अन्य जानकारी पर विचार करने के पश्चात मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसके पश्चात 'संविधान' कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है;

अतः यद्यमें संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उद्घोषणा करता हूँ कि मैं—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या तद्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने हाथ में लेता हूँ;

(ख) घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधान मण्डल की शक्तियां संसद के प्राधिकार द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी; और

(ग) निम्नलिखित प्रामांगिक और आनुषंगिक उपबन्ध करता हूं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए मुझे आवश्यक या बांछनीय प्रतीत होंगी, अर्थात् :—

- (i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खण्ड (क) के आधार पर अपने हाथ में लिये गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझू उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा;
- (ii) उस राज्य के सम्बन्ध में संविधान के निम्नलिखित उपबन्धों के प्रवृत्तन को एतद-द्वारा निलम्बित किया जाता है, अर्थात् :—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का सम्बन्ध ऐसे विधेयक को जो उसमें निर्दिष्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मण्डल को निर्वंशित करने से है;

अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध भारत के नियंत्रक और महालेखपरीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है;

अनुच्छेद 163 और 164;

अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राज्य सरकार के कार्य के मंत्रियों के बीच बटवारे से है; अनुच्छेद 167;

अनुच्छेद 169 के खण्ड (1) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प पारित किये जाने से है;

अनुच्छेद 174 का खण्ड (1), अनुच्छेद 175, 176 और 177, अनुच्छेद 179 का खण्ड (ग) और उसका प्रथम परन्तुक, अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 183 का खण्ड (ग) तथा उसका परन्तुक, अनुच्छेद 185, 188, 189, 193, 194 तथा 196 से 198 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 200 और 201, अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) का परन्तुक तथा खण्ड (3) का परन्तुक; और अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध ज्ञापन संहित प्रतिवेदन को राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है;

- (iii) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उस राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के प्रति निर्देश लगाया जायेगा और उसमें राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति किसी निर्देश का जहां तक उसका सम्बन्ध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ, जब तक कि सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो संसद के प्रति निर्देश

लगाया जायेगा और विशिष्टतया अनुच्छेद 313 में राज्यपाल और राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति निर्देश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद या उसके सदनों के प्रति निर्देश लगाया जाएगा;

परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये बोनों भी सम्मिलित हैं) अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा छिंतीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये बोनों भी सम्मिलित हैं) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को इस खण्ड के उपखण्ड (१) के अधीन उस सीमा तक जहाँ तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निर्वाचित करेगी;

(iv) संविधान में उस राज्य के विधान मण्डल के या उद्घारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानों उसके अन्तर्गत इस उद्घोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निर्देश है, सभा संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (1904 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं० 1), और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10वां) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होना मानों यह उस राज्य के विधान मण्डल का अधिनियम हो ।

शिविर कीव

ब० ब० श० शिरि,

(य० एस० एस० प्रार०)

राष्ट्रपति ।

1 अक्टूबर, 1970

[सं० 38/12/70-पोल० प्राई० (ए०)]

नई दिल्ली;

एल० पी० सिंह,

2, अक्टूबर, 1970

सचिव ।

आवेदन

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर, 1970

जी० एस० आर० 1757.—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित भादेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज 1970 के अक्टूबर मास के प्रथम दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्-द्वारा निदेश देता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य के राज्यपाल में निहित या एतद्द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के अधीन पर अपने हाथ में ले लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

शिविर कीव

(यू० एस० एस० आर०)

1 अक्टूबर, 1970

य० व० गिरि,

राष्ट्रपति ।

[स० 38/12/70—पोल० आई० (ए०)]

एल० पी० सिंह,

सचिव ।

नई दिल्ली,
2 अक्टूबर, 1970